विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2014 में किसानों की आय कितनी थी और अब किसानों की आय कितनी है?	जी हाँ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर तैयार की गयी डबलिंग फार्मर्स इनकम वैल्यूम-2 के पृष्ठ-27 पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कृषक हाउसहोल्ड की औसत आय (2011-12 मूल्य पर) वर्ष 2014-15 में रूपये 52731 वार्षिक थी । भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी ''ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019'' के अनुसार कृषक हाउसहोल्ड की औसत वार्षिक आय (जुलाई, 2018-जून, 2019) में रूपये 96732 रही है।
(ख) क्या किसानों की आय दोगुनी हो गयी है ?	जी हाँ। प्रदेश में कृषकों के सतत् उन्नयन एवं कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास दर में वृद्धि कराना भी है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रु0/कु0 था, जो बढ़कर 2022-23 में 2040 रु0/कु0 हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2014-16 में गेंहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रु0/कु0 था, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2125 रु0/कु0 हो गया है। इसी प्रकार अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार को प्रस्तावित करती है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम कृषि विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से संचालित है, जिसमें कुल कार्य योजना का 70 प्रतिशत कृषि विभाग द्वारा एवं 30 प्रतिशत यूपीडास्प द्वारा कार्यक्रम संचालित किये जाते है। योजनान्तर्गत दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कैफेटेरिया के आधार पर

	प्रोत्साहन स्वरूप कृषकों को अनुदान दिये जाते हैं। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत है- (1) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। (2) नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन एण्ड टेक्नालॉजी। (3) नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0)। (4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। (5) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। (6) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। (7) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सिंचन क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के सतत् प्रयास से किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।